



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था की बहु-गति विकास दर जारी है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, निजी क्षेत्र में उत्साहहीनता एवं यूरो क्षेत्र के संकट के कारण विकास की गति प्रभावित हुई है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि दर्ज हुई है पर इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। अमरीका में कुल मिलाकर आर्थिक परिवेश में सुधार हो रहा है, यूरोप में हल्की मंदी की स्थितियाँ बनती दिख रही हैं परन्तु दूसरी ओर विकास की धीमी गति के बावजूद भारत एवं चीन की अर्थव्यवस्थाओं से अभी भी यह उम्मीद है कि वे इस गिरती वैश्विक विकास दर को कुछ संबल प्रदान कर पाएंगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था का जहाँ तक संबंध है, वित्त वर्ष 12 में जीडीपी की संवृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 11 में यह दर 8.4% रही थी। इन सबके बावजूद, भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही भारत अभी भी निवेश के लिए एक पसंदीदा देश बना हुआ है जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि यहाँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वित्त वर्ष 12 में बढ़कर 46.85 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुँच गया जबकि वित्त वर्ष 11 में यह 34.85 बिलियन अमरीकी डॉलर था। विशेष रूप से दिसंबर 2011 में एनआरआई जमाओं पर ब्याज की दरों को अविनियमित करने के बाद एनआरआई जमाशियाँ वित्त वर्ष 12 में पर्याप्त रूप से बढ़कर 11.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गईं। वित्त वर्ष 11 में ये केवल 3.24 बिलियन डॉलर ही थीं। विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा धन प्रेषण की स्थिति भी तगड़ी रही तथा वर्ष 11 में इनके द्वारा 63.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का धन प्रेषण देश में किया गया जो विकासशील देशों में सर्वाधिक था।

वित्त वर्ष 12 के दौरान कृषि एवं सेवाओं के क्षेत्र में निष्पादन अच्छा बना रहा परन्तु औद्योगिक उत्पादन की गति में विशेष रूप से निर्माण के क्षेत्र में शिथिलता साफ दिखाई दी। घरेलू एवं वैश्विक कारणों से निवेश प्रभावित हुआ जिसका प्रतिकूल प्रभाव निर्माण गतिविधियों पर पड़ा और समग्र औद्योगिक संवृद्धि दर वित्त वर्ष 11 के 6.8% से घटकर वित्त वर्ष 12 में 2.6% रह गयी। अच्छे मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई हालांकि विगत उच्च दर के कारण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जीडीपी संवृद्धि दर वित्त वर्ष 11 के 7.0% की तुलना में वित्त वर्ष 12 में गिरकर 2.8% रह गई। पर सेवा क्षेत्र में पर्याप्त स्थिरता बनी रही जो कि वित्त वर्ष 11 के 9.2% की तुलना में वित्त वर्ष 12 में 8.5% की गति से बढ़ा।

विदेश व्यापार के क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में धीमेपन के बाद भी निर्यातों में 21% की वृद्धि हुई। यद्यपि आयातों में 32% की उच्च वृद्धि के कारण व्यापार अंतर 185 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया जिसकी प्रमुख वजह स्वर्ण एवं तेल के आयातों में वृद्धि रही। विदेशी वाणिज्यिक ऋणों एवं

धीमी हो रही संवृद्धि के बावजूद, भारत और चीन द्वारा अब भी वैश्विक सुधार के लिए संबल प्रदान किए जाने की संभावना है।

अल्पावधि ऋणों में वृद्धि के कारण विदेशी ऋणों में वृद्धि हुई है। एनआरआई जमाओं में वृद्धि भी भारत के विदेशी ऋणों में वृद्धि का एक कारण रही है।

मुद्रास्फीति की दर भी चिंता का विषय रही है जो वित्त वर्ष 11 के 9.6% की तुलना में वित्त वर्ष 12 में कुछ कम होकर 8.8% पर आ गई है। इस कारण भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ कड़े मौद्रिक उपाय करने पड़े। मई एवं अक्टूबर 2011 के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाँच बार रेपो रेट बढ़ाई जो 7.25% से बढ़कर 8.50% कर दी गई है। नकदी की स्थिति घाटे की बनी रही है तथा बैंकों को नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत ऋण लेते देखा गया है। नकदी पर दबाव कम करने और पर्याप्त ऋण उपलब्धता बनाए रखने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमांत स्थायी ऋण सुविधा प्रारंभ की है तथा सीआरआर को 50 बीपीएस एवं 75 बीपीएस की दो किस्तों में 125 बीपीएस तक कम किया है जो वर्ष के दौरान 6.0% से घटकर 4.75% रह गई है।

बैंकिंग घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कड़े मौद्रिक उपायों के कारण बैंकों की व्यवसाय वृद्धि प्रभावित हुई है जो उनकी जमा एवं ऋण वृद्धि में हुई कमी के माध्यम से परिलक्षित होती है। जहाँ एक ओर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) की जमा संवृद्धि दर ब्याज की दरों में वृद्धि के बावजूद भी वित्त वर्ष 11 के 15.9% से घटकर वित्त वर्ष 12 में 13.4% पर आ गई है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ऋण वृद्धि की दर वित्त वर्ष 11 के 21.5% से कम होकर वित्त वर्ष 12 में 17.0% रह गई है जो अर्थव्यवस्था में विकास की कम गति की द्योतक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 12 के दौरान पाँच बार रेपो रेट बढ़ाई है जो 7.25% से बढ़कर 8.50% पर आ गई है। मौद्रिक प्रसार की परिणति के रूप में बैंकों की जमाशियों के साथ साथ ऋणों पर ब्याज की दरें भी बढ़ गई हैं। एक वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाली सभी जमाओं पर प्रमुख बैंकों ने ब्याज की दरें वित्त वर्ष 11 के 7.75-9.50% से बढ़ाकर वित्त वर्ष 12 में 8.50-9.25% के बीच रखी है। इसके अलावा, सभी प्रमुख बैंकों ने अपनी आधार दरों को भी इसी अवधि में 8.25-9.50% से बढ़ाकर 10.00-10.75% तक के स्तर पर रखा है। वृद्धि दर में आने वाली गिरावट के कारण कारपोरेट लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा है तथा एनपीए की पहचान के लिए प्रणाली प्रचालित व्यवस्था अपनाए जाने के कारण वर्ष के दौरान बैंक की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई है।

अवसर एवं चुनौतियाँ

सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास में अपना निवेश बढ़ा रही है, वित्तीय समावेशन में विस्तार कर रही है तथा विनिर्माण एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है जिससे अंततः विभिन्न क्षेत्रों में विकास के



DIRECTORS' REPORT

Management Discussion and Analysis

ECONOMIC BACKDROP AND BANKING ENVIRONMENT

The global economy continued to be characterised by multi-speed growth as fiscal consolidation, private sector deleveraging and the Euro zone crisis affected growth in advanced economies. Emerging market economies are growing but at a slower pace than expected earlier. Overall, conditions in the US are improving, Europe is sliding into a mild recession, but despite slowing growth, India and China are still likely to provide some support for global recovery.

For the Indian economy, GDP growth in FY'12 is estimated at 6.5% against 8.4% in FY'11. Notwithstanding this, India remained one of the fastest growing economies in the world. India also remained a favoured destination for investment which is reflected in increase in FDI to US\$ 46.85 billion in FY'12 against US\$ 34.85 billion in FY'11. NRI deposits grew substantially to US\$ 11.0 billion in FY'12 from US\$ 3.24 billion in FY'11, particularly after deregulation of interest rates on NRI deposits in December 2011. Remittances from Indians working abroad remained robust at US\$ 63.7 billion in 2011, the highest among developing countries.

During FY'12, agriculture and services continued to perform well but industrial production particularly in manufacturing slowed perceptibly. Investment was impacted by domestic and global factors, which affected manufacturing activity and overall industrial growth decelerated to 2.6% in FY'12 from 6.8% in FY'11. Good monsoons led to increase in food grains production though the deceleration in agriculture and allied sector GDP growth to 2.8% in FY'12 from 7.0% in FY'11 was due to high base effect. Services sector however, remained fairly stable and grew by 8.5% in FY'12 against 9.2% in FY'11.

On the external front, exports grew by 21% despite slowdown in global trade. However, the trade gap widened to \$185 billion due to higher import growth at 32% led by sharp increase in gold and oil imports. Rise in external debt was driven by increase in external

Despite slowing growth, India and China still likely to provide support for global recovery

commercial borrowings, export credit and short-term debt. Increased flows of NRI deposits also have implications for India's external debt.

Inflation remained a concern with average inflation at 9.6% in FY'11 moderating only slightly to 8.8% in FY'12, prompting RBI to follow a tight monetary policy. Between May and October 2011, RBI increased the Repo rate five times from 7.25% to 8.50%. The liquidity situation remained in deficit mode and banks were seen borrowing under the Liquidity Adjustment Facility (LAF). To ease pressure on liquidity and ensure adequate credit availability, RBI introduced the Marginal Standing Facility (MSF) and cut CRR by 125 bps in two tranches of 50 bps and 75 bps from 6.0% to 4.75% during the year.

Banking Developments

The moderation in GDP growth following monetary tightening by RBI affected business growth of banks, which is reflected in slowdown in their deposit and credit growth. While deposit growth of All Scheduled Commercial Banks (ASCB) decelerated to 13.4% in FY'12 from 15.9% FY'11 despite increase in interest rates, growth in ASCB credit was lower at 17.0% in FY'12 than 21.5% in FY'11 reflecting slower growth in the economy. To control inflation, RBI raised the repo rate five times during FY'12 from 7.25% to 8.50%. Reflecting monetary transmission, interest rates on bank deposits and credit also rose. Deposit rate of major banks for more than one year maturity rose from 7.75-9.50% in FY'11 to 8.50-9.25% in FY'12, and base rate of major banks rose from 8.25-9.50% to 10.0-10.75% in the same period. Due to deceleration in growth impinging on corporate profitability and move to system-driven identification of NPAs, non-performing assets of banks rose during the year.

Opportunities and Threats

The Government is increasing investment in agriculture and rural development, expanding financial inclusion and pushing for investment in manufacturing and infrastructure, which will translate into growth

**24.62%****परिचालन लाभ में संवृद्धि**

अवसर बढ़ने वाले हैं जैसे इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम आदि। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 13 के दौरान दरों में कमी लाने की संभावनाएं हैं, यद्यपि दरों में कमी की सीमा मुद्रास्फीति के रूझान पर निर्भर करेगी। इन सब उपायों के कारण बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने निधि एवं निधीतर व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रमुख नीतिगत दर में कमी किए जाने के कारण बैंकों को भी उसी परिमाण में अपनी ब्याज दरों में कमी लानी होगी। पिछले वर्ष उच्च लागत पर निधियाँ जुटाए जाने और बड़ी अनर्जक आस्तियों एवं पुनर्संचित आस्तियों के कारण बैंकों के लिए रेपो दर में आई कमी के सम्पूर्ण प्रभाव को ग्राहकों की ओर बढ़ाना कठिन होगा। वित्तीय आस्तियों में बचत की घटती प्रवृत्ति के कारण जमाओं की वृद्धि दर में आई कमी के चलते बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन पर काफी दबाव रहेगा क्योंकि घरेलू लोग आजकल स्वर्ण एवं रियल इस्टेट में निवेश करना अधिक पसंद कर रहे हैं।

भावी परिदृश्य

वित्त वर्ष 13 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन वित्त वर्ष 12 की तुलना में बेहतर होने की संभावना है। हमारा यह विश्वास है कि वित्त वर्ष 12 की चौथी तिमाही में जीडीपी अपने न्यूनतम स्तर 5.3% को देख चुकी है तथा इसके अब गति पकड़ने की संभावना है। हमारा यह भी मानना है कि आर्थिक परिवेश में परिवर्तन को औद्योगिक विकास की गति प्रचालित करेगी विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में जहाँ सरकार अपनी विनिर्माण नीति के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ा रही है तथा विकास को गति देने के लिए कुछ बड़ी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है जिससे देश में निवेश के परिवेश में सुधार आएगा और जमीनी स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में लगातार दूसरे वर्ष खाद्यान्नों का रेकार्ड उत्पादन हुआ है तथा वित्त वर्ष 12 में इसके 250.40 मिलियन टन के स्तर को छूने की संभावना है जिस कारण खाद्य पदार्थों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव कुछ कम रह सकता है। तदनुसार, हमने 2012-13 के दौरान कुछ उच्चतर जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है। हमारा यह मत है कि इस विकास को गति देने की प्रक्रिया में बैंकों की जमाराशियों एवं ऋणों की मात्रा में वृद्धि होगी।

जोखिम एवं चिन्ताएं

आर्थिक परिवेश को सबसे बड़ा खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंथर गति से है क्योंकि यूरो क्षेत्र में ऋण संकट जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल एवं कर्मांडिटी की बढ़ती कीमतों से विकास की गति नरम पड़ सकती है। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में नकदी झोंकने और बैंकों के कम उपयोग को रोकने के कारण भारत को पूँजी प्रवाहों की अस्थिर गति एवं आस्तियों के निरंकुश ढंग से बढ़ते स्तर के प्रति सचेत रहना होगा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा जोखिम को कम करने एवं

बैंकों के नियंत्रण को घटाने के उपायों के लौटने से यह स्थिति और कठिन हो सकती है।

मानसून, खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति एवं ईंधन के मूल्यों के कारण प्रच्छन्न मुद्रास्फीति, चालू खाते में बढ़ते घाटे और बढ़ते राजकोषीय गिरावट जैसे प्रमुख जोखिमों के कारण राजकोषीय घाटे की स्थिति बन रही है। वित्त वर्ष 13 में राजकोषीय घाटा 5.1% तक रहने का अनुमान है परन्तु कर संग्रहण एवं विनिवेश आगम में कमी की वजह से राजस्व में कमी के साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी के चलते सरकार की निवल बाजार उधार राशियाँ ₹4.79 लाख करोड़ के लक्ष्य से ऊपर जा सकती हैं। बढ़ती तेल की कीमतें एवं वैश्विक मांग में कमी के कारण घटते निर्यातों के चलते वित्त वर्ष 13 में चालू खाता घाटे के और बढ़ने की आशंका है।

संवृद्धि की धीमी रफ्तार के चलते आपूर्ति की बाधाओं के रहते मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। नकदी की कमी चिंताजनक बनी रहेगी तथा बैंकों को इस स्थिति में नकदी के दबाव का सामना करने के लिए अपने पुनर्वित्त के संसाधनों के अलावा भी बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने पड़ सकते हैं। समग्र रूप से यदि देखा जाए तो हमारे बड़े घरेलू बाजार के बड़े आकार, उच्च घरेलू बचत दर और निवेश की व्यापक संभावनाओं, जो कि हमारी ताकतें हैं, के बाद भी भारत की विकास दर अपेक्षाओं से कम रहने की संभावना बनी हुई है।

वित्तीय निष्पादन

लाभ

वर्ष 2011-12 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹31,573.54 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹25,335.57 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 24.62% की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2011-12 के लिए बैंक को ₹11,707.29 करोड़ का निवल लाभ हुआ जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹8,264.52 करोड़ रहा था। इस प्रकार इसमें 41.66% की वृद्धि दर्ज हुई।

यद्यपि निवल ब्याज आय में 33.10% की वृद्धि हुई, परन्तु अन्य आय में 9.31% की गिरावट आई। परिचालन व्ययों में 13.27% की वृद्धि दर्ज की गई। परिचालन व्ययों में यह वृद्धि उच्चतर स्टाफ लागत और अन्य खर्चों के कारण हुई।

लाभांश

बैंक ने ₹35.00 प्रति शेयर की दर से (350%) लाभांश घोषित किया जबकि पिछले वर्ष यह ₹30.00 प्रति शेयर (300%) था।



opportunities for several sectors such as steel, cement, aluminium, etc. To boost growth, RBI is likely to cut rates further during FY'13, though the extent of rate cuts will be contingent on the inflation trajectory. All this will provide an opportunity for banks to increase fund and non-fund business in a wide range of areas.

Banks will be required to cut interest on credit in tandem with cut in key policy rate by RBI. However, due to high cost funds mobilised over the last year and large NPAs and restructured assets, banks may find it difficult to pass on the entire reduction in repo rate to customers. Net Interest Margin (NIM) of banks could come under pressure as it may be difficult for banks to cut interest rates on deposits due to sluggish deposit growth reflecting the declining trend in savings in financial assets as households favour physical assets like gold and real estate.

Outlook

In FY'13, the Indian economy is expected to perform better than in FY'12. We believe GDP growth bottomed out in Q4 FY'12 at 5.3%, and economic growth is now gaining traction. The change in the economic environment will be led by industrial growth, particularly in the manufacturing sector, as we believe the Government's New Manufacturing Policy, increased spending in the infrastructure space and efforts to push through some large projects to kick start growth will help improve the investment climate and attract FDI on the ground. The country has seen record food grains harvest for the second successive year and food grains output is likely to touch 250.40 million tonnes in FY'12, which will have a moderating impact on food inflation. Accordingly, we have pencilled in slightly higher GDP growth in 2012-13. To support this growth, in our view, banking sector deposits and credit are poised to grow in tandem.

Risks and Concerns

The main risks to the outlook are slowing global growth as the Euro zone sovereign debt crisis continues. High international oil and commodity prices could also dampen growth. As a result of the vast pools of liquidity injected by central banks of advanced countries to stimulate growth and prevent bank deleveraging, India will need to guard against volatile capital flows and build-up of asset bubbles. The situation could be exacerbated by the return of risk aversion and deleveraging by banks in developed economies.

24.62%

Growth in Operating Profit

Monsoons, inflation including food inflation and suppressed inflation on account of fuel prices, widening current account deficit, and fiscal slippage leading to higher fiscal deficit are major risk factors. The fiscal deficit is estimated to be 5.1% in FY'13 but slower revenue generation through tax collections as well as disinvestment proceeds, and rise in expenditure can lead to higher net market borrowings by the Government than the targeted ₹4.79 lakh crore. Rising oil prices, as also slowing export growth due to weakness in global demand could lead to widening of the current account deficit in FY'13.

Inflation could rise on the back of supply constraints from a slowdown in growth. Liquidity is likely to remain a concern and banks may need to strive for higher resources mobilisation besides tapping all sources of refinance, to avoid liquidity pressure. Overall, the biggest concern is that despite strengths such as a large domestic market, high domestic savings rate and vast scope for investment, India's growth remains below its potential.

FINANCIAL PERFORMANCE

Profit

The Operating Profit of the Bank for 2011-12 stood at ₹31,573.54 crores as compared to ₹25,335.57 crores in 2010-11 registering a growth of 24.62%. The Bank has posted a Net Profit of ₹11,707.29 crores for 2011-12 as compared to ₹8,264.52 crores in 2010-11 registering a growth of 41.66%.

While Net Interest Income recorded a growth of 33.10%, the Other Income declined by 9.31%, Operating Expenses increased by 13.27% attributable to higher staff cost and other expenses.

Dividend

The Bank has declared dividend @ ₹35.00 per share (350%) as against @ ₹30.00 per share (300%) in the previous year.



निवल ब्याज आय

बैंक की निवल ब्याज आय में 33.10% की वृद्धि हुई और वर्ष 2011-12 में यह बढ़कर ₹43,291.08 करोड़ पर पहुँच गई जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹32,526.41 करोड़ रही थी।

वर्ष के दौरान वैश्विक परिचालनों से सकल ब्याज आय ₹81,394.36 करोड़ से बढ़कर ₹1,06,521.45 करोड़ हो गई और इस प्रकार इसमें 30.87% की वृद्धि दर्ज हुई।

अग्रिमों की राशि अधिक रहने से भारत में अग्रिमों पर ब्याज आय वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹77,309.15 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹56,960.97 करोड़ थी। भारत में अग्रिमों पर औसत आय वर्ष 2010-11 के 9.56% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 11.05% हुई। विदेश स्थित कार्यालयों के अग्रिमों पर ब्याज आय में भी 24.99% वृद्धि हुई।

भारत में कोषीय परिचालनों में निविष्ट संसाधनों से आय में 22.05% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण निविष्ट औसत संसाधनों की मात्रा और औसत आय में वृद्धि होना था। यह औसत आय, जो वर्ष 2010-11 में 7.02% थी, वर्ष 2011-12 में बढ़कर 7.51% पर पहुँच गई।

वैश्विक परिचालनों का कुल ब्याज व्यय वर्ष 2010-11 में ₹48,867.96 करोड़ था, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 63,230.37 करोड़ पर पहुँच गया। भारत में जमाराशियों पर ब्याज व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में 29.19% की वृद्धि हुई, जबकि भारत में जमाराशियों के औसत स्तर में 14.31% की वृद्धि हुई थी। जमाराशियों की औसत लागत वर्ष 2010-11 के स्तर 5.26% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 5.95% हो गई।

गैर-ब्याज आय

वर्ष 2011-12 में गैर-ब्याज आय की राशि ₹14,351.45 करोड़ रही, जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹15,824.59 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें 9.31% की गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत और विदेश में स्थित अपने सहयोगी बैंकों/अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश के रूप में ₹767.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹827.73 करोड़) प्राप्त किए।

परिचालन व्यय

उच्चतर पेंशन प्रावधान करने और स्टाफ संख्या में वृद्धि होने के कारण स्टाफ लागत में 11.59% की वृद्धि हुई और वर्ष 2011-12 में इसकी राशि ₹16,974.04 करोड़ रही जबकि वर्ष 2010-11 में यह ₹15,211.62 करोड़ रही थी। अन्य परिचालन व्ययों में भी 16.54%



33.10%

निवल ब्याज आय

की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण भाड़े, करों और बिजली, डाक खर्च, तार व टेलीफोन, बीमा तथा विविध व्ययों में वृद्धि होना था।

परिचालन व्यय, जिसमें स्टाफ लागत और अन्य परिचालन व्यय शामिल है, में पिछले वर्ष की तुलना में 13.27% की वृद्धि हुई।

प्रावधान और आकस्मिकताएँ

वर्ष 2011-12 में किए गए प्रावधानों की मुख्य राशियाँ निम्नानुसार रही:

- विनिधानों पर मूल्यहास के संबंध में ₹663.70 करोड़ का प्रावधान किया गया (जबकि वर्ष 2010-11 में विनिधानों पर मूल्यहास से संबंधित प्रतिलेखन की राशि ₹646.75 करोड़ रही थी)। इसमें 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी पर प्रीमियम के परिशोधन को शामिल नहीं किया गया।
- ₹455.93 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर, कर प्रावधान के लिए ₹6,320.09 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹5,712.89 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर ₹976.82 करोड़ था)।
- ₹11,545.85 करोड़ (राइट बैंक को छोड़कर) अनर्जक आस्तियों के लिए (वर्ष 2010-11 में ₹8,792.09 करोड़ था)।
- मानक आस्तियों के लिए ₹978.81 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹976.60 करोड़)। वर्तमान वर्ष के प्रावधान सहित मानक आस्तियों पर किए गए कुल प्रावधान की राशि ₹4,296.03 करोड़ थी।

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष

- ₹3,516.98 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹2,479.36 करोड़) की राशि सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।
- ₹14.38 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹9.61 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित की गई।
- ₹5,536.50 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹2,729.86 करोड़) की राशि अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।



Net Interest Income

The Net Interest Income of the Bank registered a growth of 33.10% from ₹32,526.41 crores in 2010-11 to ₹43,291.08 crores in 2011-12. This was due to higher growth in the advances and investment portfolios.

The gross interest income from global operations correspondingly rose from ₹81,394.36 crores to ₹1,06,521.45 crores during the year registering a growth of 30.87%.

Interest income on advances in India registered an increase from ₹56,960.97 crores in 2010-11 to ₹77,309.15 crores in 2011-12 due to higher volumes. The average yield on advances in India increased from 9.56% in 2010-11 to 11.05% in 2011-12. Interest income on advances at foreign offices has also grown by 24.99%.

Income from resources deployed in treasury operations in India increased by 22.05% mainly due to higher average resources deployed and increase in average yield. The average yield, which was 7.02% in 2010-11, has increased to 7.51% in 2011-12.

Total interest expenses of global operations increased from ₹48,867.96 crores in 2010-11 to ₹63,230.37 crores in 2011-12. Interest expenses on deposits in India during 2011-12 recorded an increase of 29.19% compared to the previous year, whereas the average level of deposits in India grew by 14.31%. The average cost of deposits has consequently increased from 5.26% in 2010-11 to 5.95% in 2011-12.

Non-Interest Income

Non-interest income stood at ₹14,351.45 crores in 2011-12 as against ₹15,824.59 crores in 2010-11 registering a decline of 9.31%.

During the year, the Bank received an income of ₹767.35 crores (₹827.73 crores in the previous year) by way of dividends from Associate Banks/subsidiaries and joint ventures in India and abroad.

Operating Expenses

There was an increase of 11.59% in the Staff Cost from ₹15,211.62 crores in 2010-11 to ₹16,974.04 crores in 2011-12. Other Operating Expenses have also registered an increase of 16.54% mainly due to



33.10%
Net Interest Income

increase in expenses on rent, taxes and lighting, postage, telegrams & telephones, insurance and miscellaneous expenditure.

Operating Expenses, comprising both staff cost and other operating expenses, have registered an increase of 13.27% over the previous year.

Provisions and Contingencies

Major amounts of provisions made in 2011-12 were as under:

- ₹663.70 crores towards provision for depreciation on investments, **excluding** amortization of premium on 'Held to Maturity' category (as against ₹646.75 crores towards depreciation on investments in 2010-11).
- ₹6,320.09 crores towards Provision for Tax, excluding deferred tax reversal of ₹455.93 crores (as against ₹5,712.89 crores in 2010-11 excluding deferred tax reversal of ₹976.82 crores).
- ₹11,545.85 crores (net of write-back) for non-performing assets (as against ₹8,792.09 crores in 2010-11).
- ₹978.81 crores towards Standard Assets (as against ₹976.60 crores in 2010-11). Including the current year's provision, the total provision held on Standard Assets amounts to ₹4,296.03 crores.

Reserves and Surplus

- An amount of ₹3,516.98 crores (as against ₹2,479.36 crores in 2010-11) was transferred to Statutory Reserves.
- An amount of ₹14.38 crores (as against ₹9.61 crores in 2010-11) was transferred to Capital Reserve Fund.
- An amount of ₹5,536.50 crores (as against ₹2,729.86 crores in 2010-11) was transferred to Other Reserve Funds.



तालिका : प्रमुख निष्पादन संकेतक

संकेतक	एसबीआई		एसबीआई समूह	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
औसत आस्तियों पर आय (%)	0.71	0.88	0.70	0.89
ईक्विटी पर आय (%)	12.84	14.36	12.92	14.84
आय की तुलना में (%) (कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	47.60	45.23	58.32	53.42
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	1013.82	1214.78	1302.70	1540.64
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	130.16	184.31	168.28	241.55
प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन (₹)	130.16	184.31	168.28	241.55
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-I)	10.69	12.05	11.02	11.84
श्रेणी-I	6.93	8.50	7.20	8.30
श्रेणी-II	3.76	3.55	3.82	3.54
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-II)	11.98	13.86	12.26	13.68
श्रेणी-I	7.77	9.79	8.02	9.65
श्रेणी-II	4.21	4.07	4.24	4.03
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.63	1.82	1.56	1.81

आस्तियाँ

बैंक की कुल आस्तियों में 9.13% की वृद्धि हुई और ये मार्च 2012 के अंत तक बढ़कर ₹13,35,519.23 करोड़ हो गईं, जबकि मार्च 2011 के अंत में ये ₹12,23,736.20 करोड़ थीं। इसी अवधि के दौरान, संविभाग में 14.65% की वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹7,56,719.45 करोड़ से बढ़कर ₹8,67,578.89 करोड़ हो गई। मार्च 2012 के अंत में विनिधानों में 5.61% की वृद्धि हुई और इनकी राशि बढ़कर ₹3,12,197.61 करोड़ पर पहुँच गई जबकि पहले यह ₹2,95,600.57 करोड़ रही थी। अधिकांश विनिधान घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों और सहयोगियों व अनुषंगियों में किया गया।

देयताएँ

बैंक की कुल देयताएँ (पूँजी एवं आरक्षितियों को छोड़कर) 8.01% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2012 को ₹12,51,568.03 करोड़ हो गई जबकि 31 मार्च 2011 को ये ₹11,58,750.16 करोड़ थीं। देयताओं में यह वृद्धि मुख्यतया जमाराशियों और उधारराशियों में वृद्धि होने के कारण हुई। 31 मार्च 2012 को वैश्विक जमाराशियों में 31 मार्च 2011 की तुलना में 11.75% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2012 को ये ₹10,43,647.36 करोड़ पर पहुँच गई जबकि 31 मार्च 2011 को ये ₹9,33,932.81 करोड़ रही थी।

मुख्य परिचालन**1. व्यवसाय समूह****क. वैश्विक बाजार परिचालन**

कारपोरेट केन्द्र में स्थित वैश्विक बाजार विभाग बैंक की चलनिधि का कार्य देखता है और ग्राहकों को विदेशी मुद्रा सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, यह भारतीय रिज़र्व बैंक की रिज़र्व संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के कार्य की देखरेख भी करता है। डेरीवेटिव्स, स्वर्ण वायदा और संविभाग प्रबंधन सेवाएँ जैसे उत्पाद उपलब्ध कराता है और बैंक की प्रोप्राइटी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी देखता है।

चलनिधि प्रबंधन कार्य और ऋण संविभाग का निष्पादन ब्याज दर उतार-चढ़ाव और अर्थव्यवस्था में चलनिधि की स्थिति पर निर्भर करता है। वित्त वर्ष 2012 में मुद्रास्फीति एवं नकदी के संकट के कारण ब्याज की दरें अस्थिर रही हैं। वर्ष की दूसरी छमाही में बैंकिंग व्यवस्था में तरलता का संकट और गहराता नज़र आया। इस परिवेश के अंदर ग्लोबल बाजार चलनिधि का सक्रिय रूप से प्रबंध करता रहा और निवेशों पर प्रतिफल प्राप्त होने के प्रति आशान्वित रहा।

ईक्विटी बाजार वर्ष के अधिकांश भाग में लगातार गिरते रहे। इस कारण हमें प्रॉप्राइटी ट्रेडिंग के लिए ईक्विटियों में अपने निवेश को कम करने और इस संविभाग को फिर से संतुलित बनाने का रणनीतिक निर्णय लेना पड़ा। हम निरंतर कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं और अच्छे निवेश अवसरों की तलाश में है जिससे अनिश्चितता के माहौल में कम से कम जोखिम उठाते हुए लाभ बढ़ाए जा सके।

देश का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते और बाजार में प्रमुख सक्रिय बैंक की भूमिका को ध्यान में रखकर बैंक का प्रयास रहता है कि कारपोरेटों सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संस्थाओं से लेकर लघु और मध्यम उद्यमों को सबसे वाजिब दरें प्रस्तावित की जाएँ। इसके अतिरिक्त, फॉरेक्स ट्रेजरी अंतर बैंक बाजार में नकदी की स्थिति को आसान करता है।

इनके अलावा, बैंक कारपोरेटों को भारतीय रुपये में और विदेशी मुद्रा में डेरीवेटिव्स भी उपलब्ध कराता है जिससे नियामक शर्तों के भीतर उनके ब्याज दर और करेंसी जोखिमों का बाजार में बचाव किया जा सके।

ट्रेजरी मार्केटिंग ग्रुप बैंक द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे विभिन्न ट्रेजरी उत्पादों को अपने ग्राहकों को विपणन करता है जिससे उनके निवेशों के विनिमय दर जोखिम/ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके। विशेष रूप से ट्रेजरी मार्केटिंग में लगे हुए अधिकारी लगातार ग्राहकों के संपर्क में रहते हैं और बैंक की सलाहकारी सेवाओं के अंतर्गत बाजारों के बारे में उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। बैंक के विदेशी मुद्रा कारोबार में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान वर्षानुवर्ष 14% की वृद्धि हुई है।

**Table : Key Performance Indicators**

Indicators	SBI		SBI Group	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
Return on Average Assets (%)	0.71	0.88	0.70	0.89
Return on Equity (%)	12.84	14.36	12.92	14.84
Expenses to Income (%) (Operating Expenses to Total Net Income)	47.60	45.23	58.32	53.42
Book Value per share (₹)	1013.82	1214.78	1302.70	1540.64
Basic Earnings Per Share (₹)	130.16	184.31	168.28	241.55
Diluted Earnings Per Share (₹)	130.16	184.31	168.28	241.55
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	10.69	12.05	11.02	11.84
Tier I	6.93	8.50	7.20	8.30
Tier II	3.76	3.55	3.82	3.54
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.98	13.86	12.26	13.68
Tier I	7.77	9.79	8.02	9.65
Tier II	4.21	4.07	4.24	4.03
Net NPAs to Net Advances (%)	1.63	1.82	1.56	1.81

Assets

The total assets of the Bank increased by 9.13% from ₹12,23,736.20 crores at the end of March 2011 to ₹13,35,519.23 crores as at the end of March 2012. During the period, the loan portfolio increased by 14.65% from ₹7,56,719.45 crores to ₹8,67,578.89 crores. Investments increased by 5.61% from ₹2,95,600.57 crores to ₹3,12,197.61 crores as at the end of March 2012. A major portion of the investment was in the domestic market in government securities and investment in Subsidiaries & Associates.

Liabilities

The Bank's aggregate liabilities (excluding capital and reserves) rose by 8.01% from ₹11,58,750.16 crores on 31st March 2011 to ₹12,51,568.03 crores on 31st March 2012. The increase in liabilities was mainly contributed by increase in deposits and borrowings. The Global deposits stood at ₹10,43,647.36 crores as on 31st March 2012 against ₹9,33,932.81 crores as on 31st March 2011, representing an increase of 11.75% over the level on 31st March 2011.

CORE OPERATIONS

1. BUSINESS GROUPS

A. GLOBAL MARKETS OPERATIONS

Global Markets department mainly handles the bank's liquidity and provides foreign exchange services to customers. In addition, it also handles compliance with reserve requirements of RBI, provides products like derivatives, gold forwards and portfolio management services, and handles the bank's proprietary trading and investment portfolio.

The liquidity management function and debt portfolio's performance depend significantly on interest rate movements and system wide liquidity conditions. In fiscal year 2012, interest rates were volatile due to inflation and liquidity concerns. The second half of the fiscal saw liquidity in the banking system tighten significantly. Within this environment Global Markets continued to actively manage the liquidity and optimized returns on investment.

The equity markets continued to fall for the major part of the year prompting a strategic decision to reduce our exposure to equities for proprietary trading and rebalance the portfolio. We still continue to hold multiple strategic positions and remain on the lookout for good investment opportunities to enhance returns while maintaining a reduced risk appetite given the uncertain environment.

Being the biggest bank of the country and its role as a market maker, the bank endeavours to provide the best prices to corporates, ranging from the behemoths to emerging SMEs both in the Public and Private Sector. In addition, forex treasury facilitates liquidity in the inter-bank market.

In addition to these, the bank also provides Indian Rupee and Foreign Exchange Derivatives to corporates for hedging their interest rate and currency exposures, within the regulatory stipulations.

Treasury Marketing Group markets various treasury products offered by the Bank, to its customers to mitigate Exchange Rate Risk / Interest Rate Risk in their exposures. Dedicated Treasury Marketing Officers continuously engage with the customers bringing them various inputs about markets as part of advisory services offered by the Bank. The Bank's **forex volumes grew by 14% YoY for FY 2011-12.**



ग्लोबल मार्केट्स समूह के पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ अनुभाग, जो सबसे बड़े निधि प्रबंधन कारोबारियों में से एक है, वर्ष 1995 के बाद से विभिन्न भविष्य निधि न्यासों के सेवांत हितलाभ निधियों का प्रबंध संभालता है। यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निधियों के निवेशों का प्रबंध भी संभालता है। 31 मार्च 2012 को पोर्टफोलियो प्रबंधन अनुभाग के प्रबंध अधीन आस्तियाँ ₹2,00,000 करोड़ से भी अधिक हैं।

ख. कारपोरेट बैंकिंग समूह

बैंक के कारपोरेट बैंकिंग समूह के चार कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयाँ हैं। यथा कारपोरेट लेखा समूह, लेनदेन बैंकिंग इकाई, परियोजना वित्त एवं लीजिंग एसबीयू तथा वित्तीय संस्थान व्यवसाय इकाई।

ख.1. कारपोरेट लेखा समूह (कैग)

कैग की स्थापना वर्ष 1995 में सर्वप्रथम कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई के रूप में बैंक के कारपोरेट बैंकिंग समूह के तहत की गई थी। विगत वर्षों में कारपोरेट लेखा समूह ने देश में शीर्षस्थ कारपोरेट को सर्वोत्कृष्ट कारपोरेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के कार्यनीतिक उद्देश्यों का प्रभावशाली ढंग से प्राप्त है। लगभग पांच सौ ऐसे कारपोरेटों का कारपोरेट लेखा समूह के साथ व्यवहार है। ग्राहकों की इस सूची में प्रत्येक खंड के उद्योग दिग्गज शामिल है।

एक अत्यंत कुशल ग्राहक संबंध टीम और एक दक्ष प्रौद्योगिकी समर्पित उत्पाद-सेवा प्रदायगी तंत्र प्रत्येक कैग यूनिट के मध्य उपलब्ध है। कैग के कार्यालय सभी चारों महानगरों तथा हैदराबाद और अहमदाबाद में हैं। उपर्युक्त प्रत्येक केंद्र पर क्षेत्रीय प्रमुख का पद अब महाप्रबंधक के स्तर का कर दिया गया है जो समूह के बढ़ते कारोबार के नितांत अनुरूप है। कारपोरेट लेखा समूह के उच्च मालियत वाले ग्राहकों को देखते हुए वरिष्ठ स्तर पर संवाद की दृष्टि से सुविधाप्रद है।

कैग खातों की कुल निधि और गैर-निधि ऋण सीमाएँ ₹5,26,078 करोड़ हैं। निधि आधारित बकाया राशियाँ ₹1,08,774 करोड़ के स्तर से 15% बढ़कर वित्त वर्ष 12 में ₹1,25,286 करोड़ पर पहुँच



कोयला कारगो टर्मिनल

उच्च राशिवाले सौदे

₹10,000 करोड़ – एनटीपीसी लि.,
₹5,000 करोड़ – पावर ग्रिड कारपोरेशन और
₹2000 करोड़ टाटा-स्टील लि.

गई हैं। इसकी बैंक के कुल देशीय ऋण पोर्टफोलियो में 16% और सीएंडआई (गैर-खाद्यान्न) अग्रिमों में 31% हिस्सेदारी है।

वर्ष के दौरान गैर-निधि आधारित बकाया राशियों में भी 17% वृद्धि हुई और ये ₹1,87,062 करोड़ हो गई। कैग का फॉरेक्स कारोबार ₹8,73,416 करोड़ का है जो बैंक के देश में फॉरेक्स कारोबार का 48% है। व्यापार वित्त (एलसी और बैंक गारंटी) कारोबार में भी 30% वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 12 में कारोबार की कुल राशि ₹3,37,486 करोड़ रही। ऋणों के धीमे उठाव और नरम वित्तीय बाजार जिसमें संरचित उत्पादों के लिए बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है, कैग के परिचालन लाभ में वित्त वर्ष 12 के दौरान 31% की वृद्धि हुई और यह ₹9,808 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹12,875 करोड़ पर पहुँच गया।

कैग के लगभग 36% निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया राशियों को विदेशी रेटिंग एजेंसियों से सर्वोच्च रेटिंग ग्रेड प्राप्त हुए। कैग का अनर्जक आस्ति स्तर 31 मार्च 2012 को कुल अग्रिमों राशियों के 0.20% पर भलीभांति नियंत्रित रखा गया है।

वर्ष के दौरान कैग ने उच्च मूल्य वाले अनेक सौदों का प्रबंध किया। इनमें से कुछ को नीचे उल्लेख किया गया है। इनमें परियोजना वित्तपोषण एसबीयू के माध्यम से मंजूर किए गए मीयादी ऋण शामिल नहीं हैं।

- एनटीपीसी लि. ₹10,000 करोड़ के 12 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।
- पावर ग्रिड कारपोरेशन आप इंडिया लि. ₹5,000 करोड़ के 15 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।
- टाटा स्टील लि. ₹2,000 करोड़ के 5 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।



नेवेली लिमिटेड कारपोरेशन लि. को ₹2,500 करोड़ की सावधि ऋण सुविधा



Portfolio Management Services Section of Global Markets, one of the largest fund managers, is managing terminal benefit funds of various provident fund trusts since 1995. It also manages investments of funds of RRBs sponsored by SBI. As on 31st March 2012, Assets under management of Portfolio Management Section exceeded ₹2,00,000 crores.

B. CORPORATE BANKING GROUP

The Bank's Corporate Banking Group consists of four Strategic Business Units viz., Corporate Accounts Group, Transaction Banking Unit, Project Finance & Leasing SBU and Financial Institutions Business Unit.

B.1. Corporate Accounts Group (CAG)

CAG was set up in 1995 as the first Strategic Business Unit to be created under Corporate Banking Group of the Bank. Over the years CAG has effectively met its strategic objectives of delivering best in class Corporate Banking services to the top most corporates in the country. Nearly five hundred such corporates deal with CAG and the client list includes industry leaders in every segment.

A highly skilled Relationship team and a strong delivery platform with enabling technology support lie at the core of each CAG unit. CAG has offices in all four metros, Hyderabad and Ahmedabad. The incumbency of Regional Head at each of the above centres has been upgraded to the level of General Manager in line with the rising business profile of the group and to facilitate interaction at senior level having regard to the high profile of the CAG clients.

The total Fund and Non-Fund limits of CAG accounts stand at ₹5,26,078 crores. The Fund based outstandings grew by 15% during FY'12 from

High Value Deals

₹10,000 crores to NTPC Ltd.,
₹5,000 crores to Power Grid Corp. &
₹2,000 crores to Tata Steel Ltd.

₹1,08,774 crores to ₹1,25,286 crores. It constitutes 16% of total domestic credit portfolio and 31% of the C & I (Non-Food) advances of the Bank.

The Non-Fund based outstandings at ₹1,87,062 crores also grew by 17% during the year. CAG's FOREX business at ₹8,73,416 crores constitutes 48% of the domestic FOREX business of the Bank. Trade Finance (LC and BG) volumes also registered a growth of 30% with the volumes standing at ₹3,37,486 crores for FY'12. Despite slow pick up of credit and a tepid financial market that did not offer significant scope for structured products, CAG's operating profit grew by 31% from ₹9,808 crores to ₹12,875 crores during FY'12.

About 36% of CAG's Fund based & Non-fund based outstandings carries the highest rating grades from the external rating agencies. The NPA level of CAG is well contained at 0.20% of total advances as on 31st March 2012.

During the year CAG handled several high value deals, a few of which are listed below excluding Term loans sanctioned through PFSBU:

- NTPC Ltd.-Term Loan of ₹10,000 crores with tenor of 12 years.
- Power Grid Corporation of India Ltd.- Term Loan of ₹5,000 crores with tenor of 15 years.
- Tata Steel Ltd – Corporate loan of ₹2,000 crores with tenor of 5 years.



₹5000 crore Term Loan Facility to Power Grid Corporation of India Ltd.



Jaguar Land Rover manufacturing initiative



- भारती एयरटेल लि. - ₹2,000 करोड़ के 6 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।
- आदानी पॉवर लि. - ₹1,200 करोड़ के 8.5 वर्षीय अवधि वाले मीयादी ऋण।

बैंक ने आदानी, जेएसडब्ल्यू, टाटा आदि जैसे प्रमुख भारतीय समूहों द्वारा विदेश में किए गए अधिग्रहणों के संबंध में एक कार्यनीतिक भूमिका निभायी है।

ख.2 लेनदेन बैंकिंग इकाई (टीबीयू)

टीबीयू नकदी प्रबंध उत्पादों, व्यापार वित्तपोषण और सप्लाई चैन (डीलर/वेंडर) वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए स्थापित की गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान इसने अपने कार्य कलाप का विस्तार किया।

(1) नकदी प्रबंध उत्पाद (सीएमपी)

बैंक में सीएमपी चेक और नकदी उगाही सेवाएँ अब 701 केंद्रों पर स्थित 1133 प्राधिकृत शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। लाभांश वारंट, मल्टी सिटी चेक, आईओआई और ई-पेमेंट इत्यादि भुगतान सेवाएँ सभी शाखाओं में उपलब्ध है। सीएमपी सेंटर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., टीसीएस, टाटा मोटर्स लि., एल एंड टी, कोल इंडिया लि., ओएनजीसी आदि अनेक प्रतिष्ठित लाभांश सौदे निष्पादित किए। यह आयकर विभाग का एकमात्र रिफंड बैंकर है और वित्त वर्ष 2011-12 में 111 लाख से अधिक रिफंड रेकाउंटों के (₹36,613 करोड़) कारोबार की देखरेख की गई। सी एम पी को 43 प्रमुख मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 253 पीएओ के सभी केंद्रीय मंत्रालयों के खर्च खातों के भुगतान की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत बैंकर चुना गया है और इस संबंध में इसने एक प्रायोगिक परियोजना संचालित की है।

(2) व्यापार वित्तपोषण

एसबीआई को एशियन बैंकर पत्रिका द्वारा वर्ष 2012 के लिए 'भारत में सर्वोत्कृष्ट व्यापार वित्त बैंक' का अवार्ड दिया गया है। ई-ट्रेड एसबीआई, जो एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल है, हमारे बैंक द्वारा मार्च 2011 में शुरू किया गया है। यह ग्राहकों को व्यापार वित्तपोषण सेवाएँ शीघ्रता से और कम खर्च पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है जिससे ये दुनिया भर में किसी भी कोने से साख-पत्र, बैंक गारंटियाँ और बिल कलेक्शन/निगोसिएशन संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकें। इस समय, ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म कैग की सभी 6 शाखाओं और एमसीजी की 63 शाखाओं में चल रहा है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। 31.03.2012 तक 393 कारपोरेट ई-ट्रेड एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

(3) सप्लाई चैन वित्तपोषण

ई-वीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक वेंडर फायनैस स्कीम) एवं ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर फायनैस स्कीम) उपर्युक्त उत्पाद पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

इनके द्वारा प्रमुख औद्योगिक घरानों और उनके वेंडरों तथा डीलरों को सप्लाई चैन लेनदेन के स्वचलित भुगतान और समाधान एवं तत्काल एमआईएस सुविधा प्रदान की जाती है। देश भर में कुल 64 प्रमुख औद्योगिक घराने और 289 वेंडर तथा 1041 डीलर 31.03.2012 तक ई-वीएफएस/ई-डीएफएस प्लेटफॉर्म के तहत इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से जुड़ चुके हैं।

ख.3. परियोजना वित्तपोषण एवं लीजिंग एसबीयू (पीएफएसबीयू)

परियोजना वित्तपोषण एवं लीजिंग एसबीयू, बिजली, दूरसंचार, सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं और अन्य शहरों गैर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे धातु, सीमेंट क्षेत्र आदि परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से निश्चित सीमा में न्यूनतम परियोजना लागत पर निधि उपलब्ध कराने का कारोबार करती है।

इस विशेष इकाई को और मजबूत बनाने के लिए बैंक में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों के 19 भूतपूर्व सीईओ/निदेशकों की सेवाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया चल रही है। इस सीईओ/निदेशकों को ऊर्जा, परिवहन, खनन, दूर संचार, धातु और उर्वरक क्षेत्रों में विशेषज्ञता होगी और ये तकनीकी क्षेत्रों में सलाह देने में सहायता कर सकेंगे।

वर्ष 2011-12 के दौरान, परियोजना वित्तपोषण एसबीयू द्वारा ₹1,08,468 करोड़ (₹3,33,054 करोड़) परिव्यय वाली परियोजनाओं के वित्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करके फंड उपलब्ध कराए गए। इनमें ₹84,408 करोड़ (₹2,36,607 करोड़) का वित्तपोषण किया जाना है। कुल ₹24,976 करोड़ (₹59,209 करोड़) संस्वीकृत किए गए। परियोजना वित्तपोषण एसबीयू अन्य बैंकों के साथ ₹18,610 करोड़ (₹73,082 करोड़) के ऋण समूहन में शामिल हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान परियोजना वित्तपोषण द्वारा दी गई संस्वीकृतियों में प्रमुख हैं - नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को (₹2,500 करोड़) 1000 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाने के लिए, मेजाऊर्जा निगम लिमिटेड को (₹2,000 करोड़) 1320 मेगावाट के संयंत्र हेतु और टाटा टेलीसर्विसेज लि. को (₹2,500 करोड़) अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए।

31 मार्च 2012 को परियोजना वित्तपोषण एसबीयू के कार्यान्वयन अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में 57,788 मेगावाट (399 मेगावाट नवीकरणीय स्रोतों से) उत्पादन के लिए बिजली परियोजनाएँ, 2-लेन, 4-लेन और 6-लेन वाली 5185 किमी सड़क बनाने के लिए सड़क परियोजनाएँ; 40 एमटीपीए बहु-उद्देशीय कार्गो और 1.2 मिलियन टीईयू कंटेनर क्षमता की देखरेख के लिए नए बंदरगाह; बेंगलूर और हैदराबाद शहरों में मेट्रो परियोजनाएं तथा इसके अलावा, स्टील, सीमेंट, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीआरई आदि अनेक परियोजनाएँ भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कुल ₹15,410 करोड़ (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) (वित्त वर्ष 2011 में ₹9,670 करोड़) दिए गए।



- Bharti Airtel Ltd – Term loan of ₹2,000 crores with tenor of 6 years.
- Adani Power Ltd – Term loan of ₹1,200 crores with tenor of 8.5 years.

The Bank played a strategic role in global acquisition by major Indian Groups like, Adani, JSW, Tata etc.

B.2. Transaction Banking Unit (TBU)

TBU, with special focus on Cash Management Product, Trade Finance and Supply Chain (Dealer / Vendor) Finance has expanded its activity during the last two years.

(1) Cash Management Product (CMP)

CMP Cheque and cash collection services in the Bank are now offered through 1133 authorized branches located at 701 Centres, while payment services comprising Dividend Warrants, Multi City Cheques, IOIs and e-payment are extended through all branches. CMP Centre executed several prestigious dividend deals like Reliance Industries Ltd., TCS, Tata Motors Ltd., L&T, Coal India Ltd. ONGC etc., in 2011-12. It is the **Sole Refund Banker for Income Tax Department** and handled over 111 lakh refund records (₹36,613 crores) in FY 2011-12. CMP has been selected as the authorized banker for handling all UMEA payments for 253 PAOs relating to 43 accredited Ministries & Departments and also did the pilot.

(2) Trade Finance

SBI has been awarded the “Best Trade Finance Bank in India” Award for 2012 by The Asian Banker.

e-Trade SBI, a web-based online portal, has been launched by our Bank in March 2011 to provide the means to customers access trade finance services with speed and efficiency by enabling them to lodge Letters of Credit, Bank Guarantees and Bills Collection/negotiation requirements online from any corner of the world. Presently, the e-trade platform has been introduced in all 6 CAG Branches and 63 MCG Branches and has been well received with 393 Corporates registered under e-Trade SBI as on 31.03.2012.

(3) Supply Chain Finance

e-VFS (Electronic Vendor Financing Scheme) & e-DFS (Electronic Dealer Financing Scheme)

The above products, which are fully on electronic platform, provide automated

payment and settlement of supply chain transactions as also real time MIS to both Industrial Majors(IM) and their vendors and dealers. A total number of 64 IMs and 289 vendors and 1041 dealers across the country have been migrated to the electronic facility under the e-VFS/e-DFS platform as on 31.03.2012.

B.3. Project Finance & Leasing SBU (PFSBU)

Project Finance & Leasing SBU (PFSBU) focuses on funding large projects in infrastructure sectors like power, telecom, roads, ports, airports, other urban infrastructure as also other non-infrastructure projects in sectors like metals, cement etc., with certain threshold on minimum project cost.

In order to further strengthen this specialised outfit, Bank has engaged 19 former CEOs/ Directors of leading PSUs with domain expertise in Energy, Transport, Mining, Telecom, Metals and Fertilizer sectors to provide consultancy support in technical areas.

During 2011-12, PFSBU appraised and enabled funding of projects with outlay of ₹1,08,468 crores (₹3,33,054 crores) involving debt of ₹84,408 crores (₹2,36,607 crores). Sanctions accorded aggregated ₹24,976 crores (₹59,209 crores), while PFSBU took up syndication of debt of ₹18,610 crores (₹73,082 crores) with other banks.

Major sanctions with Project Finance during 2011-12 included Neyveli Lignite Corporation Limited (₹2,500 crores) for setting up Power plant for 1000 MW, Meja Urja Nigam Limited (₹2,000 crores) for 1320 MW and Tata Teleservices Ltd (₹2500 crores) for expansion of their services.

As on 31st March 2012, the portfolio of infrastructure projects under implementation with Project Finance SBU involves Power projects to produce 57,788 MW including 399 MW from renewable sources; Telecom Projects serving 303 million subscribers; Road projects to lay 5185 kms. of 2-lane, 4-lane & 6-lane Roads; new Ports to handle 40 MTPA multi-purpose cargo and 1.2 million TEU of container capacity ; Metro projects in the cities of Bangalore and Hyderabad besides a host of projects in steel, cement, Urban Infra, CRE etc. During the year, a total (FB + NFB) of ₹15,410 crores (₹9,670 crores in FY'11) were disbursed to these projects.



राष्ट्रीय राजमार्ग-45 उलुंडुरपेट से पैडालुर (तमिलनाडु)

वित्त वर्ष 2011-12 में सामान्यता नए निवेशों में गिरावट देखी गई। यह गिरावट खास तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऊँची ब्याज दरों और व्यवस्था संबंधी मुद्दों के चलते रही। परियोजना वित्तपोषण एसबीयू ने इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभायी।

धीमेपन के बावजूद ₹69,535 करोड़ की कुल परियोजना लागत और ₹49,465 करोड़ के ऋण वाले 43 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं जिनमें एसबीआई का हिस्सा 31.03.2012 को ₹11,643 करोड़ है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर हमारे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में चार चांद लग जाएँगे।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

ख.4. वित्तीय संस्था व्यवसाय इकाई (एफआईबीयू)

एफआईबीयू वित्तीय संस्थाओं से भविष्य में उत्पन्न होनेवाले कारोबारी अवसरों से लाभ उठाने पर विशेष रूप से ध्यान देता है। इन वित्तीय संस्थाओं में बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ, दलाली फर्म और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं। कैपिटल मार्केट शाखा, मुंबई (सीएमबी) एफआईबीयू के तहत एक विशेषीकृत शाखा है जो सभी प्रमुख एक्सचेंज और सीसीआईएल के लिए एक समाधानकर्ता बैंक है। सीएमबी ब्रोकरों और म्यूचुअल फंडों की सेटलमेंट बैंकिंग और ट्रांजेक्शन बैंकिंग की जरूरतों की देखरेख करती है। यह इश्यू बैंकर और सभी प्रमुख आईपीओ/एफपीओ/एनएफओ/बॉण्ड इश्यू जैसे एनएचएआई, हुडको, आरईसी, एनबीसीसी के एस्को कलेक्टिंग और रिफंड बैंकर का कारोबार भी संभालती है।

इस खंड की प्रमुख नई पहलों और शुरू किए गए उत्पादों में - ब्रोकरों के लिए विशेष चालू खाता उत्पाद, कासा संग्रहण के लिए हाउसिंग सोसाइटियों/एसोसिएशनों को लक्ष्य को तैयार किए गए विशेष चालू खाता उत्पाद, बड़े स्टॉक ब्रोकरों के लिए साइट टू

57,788 मेगावाट

पॉवर परियोजनाएं
कार्यान्वयन अधीन

टाइट जुड़ाव की सुविधा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए एटीएम शेयरिंग करार करना शामिल है।

एफआईबीयू द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों में जीवन बीमा कंपनियों के प्रीमियम की उगाही, स्टॉक ब्रोकरों के लिए नए जमा एवं ऋण उत्पाद आदि शामिल हैं। एफआईबीयू पूरे भारत में वित्तीय संस्थाओं को धन उगाही, भुगतान और प्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराकर कासा में बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपने विशाल नेटवर्क और टेक्नोलॉजी का उपयोग कराने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है।

ग. मध्य-कारपोरेट

1. मध्य कारपोरेट समूह मध्य कारपोरेट क्षेत्र की इकाइयों की बैंकिंग जरूरतों की पूर्ति करता था। मध्य कारपोरेट समूह के सृजन का मुख्य उद्देश्य मध्य कारपोरेट ग्राहकों को ऋण देने में लगने वाले समय में कमी लाकर उन्हें दी जानेवाली सेवा के स्तर को बेहतर बनाना, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में गुणवत्ता तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन मॉडल अपनाकर मध्य कारपोरेट ग्राहकों को बैंक के विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। 31.03.2012 के अंत में इस समूह ने विस्तार करते हुए 10 एमसीआरओ के तहत 62 शाखाएँ और ₹1,72,651 करोड़ का आस्ति आधार कर लिया है। ऐसी सभी कंपनियाँ/फर्मों जिनकी वार्षिक बिक्री/आय ₹50 करोड़ से अधिक और गैर निधि आधारित आवश्यकताएँ ₹10 करोड़ से अधिक हैं। एमसीजी के दायरे में आती हैं। ग्राहकों



बॉम्बे रेयान फैशन लि. (बीआरएफएल)



Mundra Port

Financial Year 2011-12, saw a general decline in new investments more particularly in the Infrastructure sector owing to higher interest rates and systemic issues. PFSBU plays an active role in various efforts being made by Government and other agencies to iron out the issues facing infrastructure finance.

Notwithstanding the slowdown, 43 proposals were in pipeline with aggregate Project Cost of ₹69,535 crores and debt component of ₹49,465 crores with SBI's Share likely to be ₹11,643 crores as on 31.03.2012. When completed, these projects will further add to the Infra story of our country. *(Figures in brackets represent previous year figures)*

B.4. Financial Institutions Business Unit (FIBU)

FIBU focuses on capturing potential business opportunities from financial institutions viz. Banks, Mutual Funds, Insurance companies, Brokerage Firms and NBFCs. Capital Market Branch, Mumbai (CMB), a specialized branch under FIBU, is a settlement bank for all major exchanges and CCIL. CMB has handled the settlement banking and transaction banking needs of brokers and mutual funds and has also acted as the Banker to the Issue and Escrow Collecting and Refund Banker to all major IPO/FPO/NFO/Bonds Issues including NHAI, HUDCO, REC, NBCC.

Some of the major initiatives undertaken and products launched for this segment include special current account product for brokers, special current account product for targeting housing societies / associations for mobilizing CASA, site to site integration facility for large stock brokers,

57,788 MW

Power Projects Under Implementation

ATM sharing arrangement for RRBs and Co-operative Banks.

Products being developed by FIBU include collection of premium of Life Insurance Companies, new deposit and loan products for stock brokers, etc. FIBU is focusing on leveraging our vast network and technology to increase our market share of CASA by offering collection, payment and remittance solutions to FI clients pan India.

C. MID-CORPORATE

1. MCG exclusively caters to the banking needs of the units falling under the Mid-Corporate sector. The main purpose of creation of MCG was to improve the service levels to the Mid-Corporate customers through improvement of the Turnaround Time (TAT) for credit delivery and ensuring quality in credit appraisal, as well as extension of bank's various products to the Mid-Corporate customers through Relationship Management model. As at the end of 31.03.2012, the Group has expanded to 62 branches under 10 MCROs at Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Indore, Kolkata, Mumbai, New Delhi and Pune, with an asset base of ₹1,72,651 crores. All Companies / firms whose annual sales / Income exceed ₹50 crores or whose Fund Based and Non Fund Based requirements exceed ₹10 crores are covered by MCG. Facilities are extended to the customers in



Denim Loomshed, Arvind Mills



को कैश क्रेडिट, मीयादी ऋणों, एफसीएनआरबी ऋणों, ईसीबी (हमारे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के माध्यम से), साख पत्र, बैंक गारंटियाँ, चुकौती आश्वासन पत्र, क्रेता की क्रेडिट, वेंडर वित्तपोषण, सप्लआई चेन वित्तपोषण, नकदी प्रबंध उत्पाद आदि के रूप में ग्राहकों को सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। एमसीजी की परिधि में वस्त्र, लौह, स्टील, खाद्यान्न, चीनी, इंजीनियरी, फार्मास्युटिकल्स, रत्न एवं आभूषण, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जैसे निर्माण, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह, बिजली आदि तथा व्यापार एवं सेवा क्षेत्र जैसे सभी क्षेत्रों के औद्योगिक कार्यक्रमों शामिल हैं। इस समूह का कुल व्यवसाय (निधि आधारित आस्तियों और जमाराशियों) 31.03.2012 को ₹1,97,162 करोड़ पर पहुँच गया।

- वर्ष 2011-12 के दौरान समूह द्वारा नए ग्राहकों के रूप में 397 ऋण संस्वीकृत किए और आस्तियों में कुल ₹14,466 करोड़ की वृद्धि की। इस प्रकार निधि आधारित अग्रिमों का स्तर 31.03.2011 के ₹1,61,208 करोड़ से बढ़कर 31.03.2012 को ₹1,72,651 करोड़ पर पहुँच गया। समूह द्वारा ब्याज आय के रूप में वर्षानुवर्ष 39.86% और परिचालन लाभ में 33.89% की वृद्धि दर्ज की। समूह के अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 31.03.2011 के 9.88% की तुलना में मार्च 2012 के अंत में 11.87% रही।
- समूह द्वारा ईपीसी, पीसीएफसी और ईबीआर के माध्यम से निर्यातकों को निर्यात ऋण भी उपलब्ध कराए। समूह का 31.03.2012 को कुल बकाया निर्यात ऋण ₹19,324 करोड़ थे। समूह का 31.03.2012 को कुल फॉरेक्स व्यवसाय (बिक्री एवं खरीद) ₹4,52,816 करोड़ है जबकि 31.03.2011 को ₹4,07,901 करोड़ था। समूह एलसी/बीजी/एलओसी जारी करने के साथ-साथ क्रेता ऋण सुविधा प्रदान करने जैसी सुविधाओं के माध्यम से आयातों में अपने ग्राहकों की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, समूह भारत में कंपनियों को विदेश में आस्ति/कंपनी अधिग्रहण में भी सहायता करता है और बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के माध्यम से एलओसी जारी करके विदेश में अपने ग्राहकों की विस्तार योजनाओं के लिए भी निधियाँ उपलब्ध कराता है। विगत वर्षों में, समूह ने यूएसए, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में कंपनियों ऐसे कई अभिग्रहणों में सहायता की है।
- इसके अलावा, एमसीजी औद्योगिक इकाइयों को बिक्री लक्ष्यों की आसानी से प्राप्ति सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए वेंडर वित्तपोषण और सप्लआई चेन वित्तपोषण भी कराता है।
- एमसीजी की स्टाफ संख्या मार्च 2005 के स्तर 3470 से मामूली सी बढ़कर 31.03.2012 को 3806 हो गई। प्रति कर्मचारी

व्यवसाय भी इस अवधि के दौरान चार गुना बढ़कर ₹11.98 करोड़ से ₹48.24 करोड़ पर पहुँच गया।

- इकाइयों को उनके कारोबार में तनाव का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए समूह द्वारा वर्ष के दौरान ₹3,139 करोड़ की कुल राशि के 65 खातों की पुनर्संरचना की गई।
- समूह ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के अंतर्गत 19 गतिविधियों में सक्रियता के साथ सहभागिता की। इन कार्यक्रमों में स्कूल बसों, एम्बुलेंसों, अस्थि निःशक्तों के लिए साइकिल, व्यावसायिक प्रशिक्षण उपकरण आदि के लिए ₹42.28 लाख का दान देना भी शामिल है।

उल्लेखनीय तथ्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011	31.03.2012
अग्रिम	1,61,208	1,72,651
कुल व्यवसाय	1,87,236	1,97,162
फॉरेक्स रेमिटेस	3,97,587	4,42,957
निर्यात ऋण	19,452	19,324
ब्याज आय	14,288	19,983
अन्य आय	2,345	2,482
परिचालन लाभ	15,419	20,646

घ. राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (एनबीजी)

31 मार्च 2012 को देश में स्थित 14097 शाखाओं में से 14013 शाखाएं इस समूह में हैं जिनका नियंत्रण बैंक के 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों द्वारा किया जाता है। एनबीजी में पांच कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयाँ हैं जिनमें लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमईबीयू), वैयक्तिक बैंकिंग (पीबीबीयू) रियल इस्टेट हैबिटेट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट (आरई-एच एंड एचडी), ग्रामीण बैंकिंग (आरबीयू) और सरकारी व्यवसाय (जीबीयू) शामिल हैं। राष्ट्रीय बैंकिंग समूह का 31.03.2012 को बैंक के कुल कारोबार में कुल देशीय जमाराशियों में 94.71% और कुल देशीय अग्रिमों में (खाद्यान्न और अंतर-बैंक को छोड़कर) 58.08% हिस्सा है।

राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के उल्लेखनीय तथ्य

(₹ करोड़ में)

दिनांक	31.03.2011	31.03.2012	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि
	स्तर	स्तर	सकल	(%)
जमाराशियाँ (अंतर बैंक को छोड़कर)	7,94,836*	9,15,670	1,20,834	15.20
अग्रिम राशियाँ (खाद्यान्न और अंतर बैंक को छोड़कर)	3,72,797*	4,29,843	57,046	15.30

(*इन आंकड़ों में आरबीयू के वर्ष 2011 के आंकड़े शामिल हैं)



the form of Cash Credit, Term Loans, FCNRB Loans, ECBs (through our International Banking Group), Letters of credit, Bank Guarantees, Letters of Comfort, Buyers' Credit, Vendor Finance, Supply Chain Finance, Cash Management Product etc., MCG encompasses the entire span of industrial activities in all sectors like textiles, iron, steel, food, sugar, engineering, pharmaceuticals gems & jewellery, infrastructure sector including construction, telecom, roads, ports, power etc. as well as trade and services sector. The aggregate business (Fund Based Assets and deposits) of the Group is ₹1,97,162 crores as on 31.03.2012.

2. During 2011-12 the Group sanctioned 397 loans by way of new connections aggregating an asset growth of ₹14,466 crores, thus increasing the level of Fund-based advances from ₹1,61,208 crores as on 31.03.2011 to ₹1,72,651 crores as on 31.03.2012. The Group recorded y-o-y growth of 39.86% by way of Interest Income and 33.89% in operating profit. The average yield on advances of the group stood at 11.87% as at the end of March 2012 vis-à-vis 9.88% as on 31.3.2011.
3. The Group also extends export credit to the exporters through EPC, PCFC and EBR. The aggregate outstanding export credit as on 31.3.2012 of the Group was ₹19,324 crores. The aggregate Forex business (Sales & Purchases) of the Group as on 31.03.2012 stood at ₹4,52,816 crores vis-à-vis ₹4,07,901 crores as on 31.03.2011. The Group also assists its customers in imports through facilities like issue of LC / BG / LOC as well as extension of Buyers Credit facility. Apart from this, the Group also assists Companies in India to acquire assets / companies abroad and also funds the expansion plans of its customers abroad through issuance of LOCs through the Bank's International Banking Group. Over the years, the Group has helped many such acquisitions by the companies in USA, Europe, Australia, Africa etc.
4. In addition, MCG has also extended Vendor Financing and Supply Chain Financing to the industrial units to facilitate smooth achievement of their Sales targets.
5. The Staff strength of MCG has increased marginally from 3,470 as on March 2005 to 3,806 as on 31.03.2012. The business per employee has increased over 4 times during the same period from ₹11.98 crores to ₹48.24 crores.

6. To enable the units to overcome the stress in their business, the Group has restructured 65 accounts aggregating ₹3,139 crores during the year.
7. The Group has also actively participated in 19 activities under Corporate Social Responsibility programmes encompassing donations of school buses, ambulances, cycles for orthopaedically challenged, vocational training equipments, etc., aggregating ₹42.28 lacs.

HIGHLIGHTS

(₹ in Crores)

	31.03.2011	31.03.2012
Advances	1,61,208	1,72,651
Aggregate Business	1,87,236	1,97,162
Forex Remittances	3,97,587	4,42,957
Export Credit	19,452	19,324
Intt. Income	14,288	19,983
Other Income	2,345	2,482
Operating Profit	15,419	20,646

D. NATIONAL BANKING GROUP (NBG)

National Banking Group, as on 31st March 2012, comprised of 14,013 out of 14,097 domestic branches, controlled by 14 Local Head Offices. NBG has five strategic Business Units comprising of Small & Medium Enterprises (SMEBU), Personal Banking (PBBU), Real Estate Habitat & Housing Development (RE-H & HD), Rural Banking (RBU) and Government Business (GBU). NBG's share in the total business of the Bank as on 31.03.2012 is 94.71% in total domestic deposits(excluding Inter-Bank) and 58.08% in total domestic advances (excluding Food & Inter-Bank).

NBG Highlights

(₹ in Crores)

	As On		YoY Growth	
	31.03.2011	31.03.2012	Absolute	(%)
Deposits (excl. Inter- bank)	7,94,836*	9,15,670	1,20,834	15.20
Advances (excl. Food & Inter-Bank)	3,72,797*	4,29,843	57,046	15.30

(*This figure is inclusive of RBU for the year 2011)